पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में

मेसर्स प्रकृति इंटरप्राईजेज

बनाम

सीजीएसटी और केंद्रीय उत्पाद शुल्क के मुख्य आयुक्त और अन्य

2019 की दीवनी रिट क्षेत्राधिकार मामला सं. 13976

18 जून, 2025

(माननीय न्यायमूर्ति श्री पी.बी.भजंत्री और माननीय न्यायमूर्ति श्री एस.बी.प्रा. सिंह)

विचार के लिए मुद्दा

क्या संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत रिट याचिका दिनांक 31.10.2014 के न्याय निर्णय आदेश के विरुद्ध सुनवाई योग्य है, जब याचिकाकर्ता ने निर्धारित समय सीमा के भीतर वित्त अधिनियम, 1994 की धारा 86 के तहत वैधानिक अपीलीय उपाय का लाभ नहीं उठाया और पांच वर्ष से अधिक की अस्पष्ट देरी के बाद न्यायालय का दरवाजा खटखटाया।

हेडनोट्स

भारतीय संविधान - अनुच्छेद 226 - रिट याचिका - स्थिरता - विलंब और लापरवाही - वैधानिक उपचार की उपलब्धता - निर्णय दिया गया कि, वैधानिक अपील को दरकिनार करने के लिए विवेकाधीन क्षेत्राधिकार का उपयोग नहीं किया जा सकता - पांच वर्ष की देरी और वैकल्पिक उपचार की उपलब्धता के कारण याचिका खारिज कर दी गई। पैरा 6-10 : याचिकाकर्ता वित्त अधिनियम, 1994 की धारा 86 के तहत 31.10.2014 के न्यायनिर्णयन आदेश के विरुद्ध अपील दायर करने में विफल रहा। 2019 में दायर रिट याचिका को पर्याप्त औचित्य के बिना घोर विलंब और लापरवाही के कारण खारिज कर दिया गया।

वित्त अधिनियम, 1994 – धारा 86 – वैधानिक अपील – सीमा – अनिवार्य तीन महीने की सीमा अवधि – निर्णय, सीमा के भीतर अपील दायर करने में विफलता न्यायनिर्णयन आदेश

को अंतिम बनाती है – रिट अनुरक्षणीय नहीं है। पैरा 5-7 : न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया कि याचिकाकर्ता को तीन महीने के भीतर वैधानिक अपील दायर करनी थी, जो नहीं किया गया। देरी को माफ नहीं किया गया।

न्यायिक अनुशासन – वैकल्पिक उपचार पर मिसालें – रिट क्षेत्राधिकार अपील का विकल्प नहीं है – थानसिंह पर भरोसा किया गया नाथमल , ग्लैक्सो स्मिथ क्लाइन, तिताघुर पेपर मिल्स। पैरा 7-9 : न्यायालय ने स्थापित कानून को दोहराया कि वैधानिक उपाय का अस्तित्व सामान्यतः रिट पर रोक लगाता है, जब तक कि असाधारण परिस्थितियां न दर्शाई जाएं।

विलंब और लापरवाही - रिट दाखिल करने में अत्यधिक विलंब - कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया - निर्णय दिया गया कि न्यायसंगतता आलसी वादी के पक्ष में नहीं है - याचिका खारिज। पैरा 9 : मृण्मय मैती बनाम छंदा कोले और त्रिदीप कुमार डिंगल बनाम पश्चिम बंगाल राज्य का हवाला देते हुए , अदालत ने दोहराया कि असाधारण देरी किसी मुकदमेबाज को विवेकाधीन राहत के अधिकार से वंचित करती है।

सर्वोच्च न्यायालय में लंबित मामले – कोई स्वतः राहत नहीं – केवल एसएलपी का लंबित होना समय-बाधित रिट पर विचार करने का आधार नहीं है । पैरा 10 : लंबित एसएलपी संख्या 5392/2025 (जीएमआर एयरपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड) का संदर्भ महत्वहीन माना गया, जहां देरी का कोई अन्य कारण नहीं बताया गया था।

न्याय दृष्टान्त

थानसिंह नथमल बनाम कर अधीक्षक , एआईआर 1964 एससी 1419;तिताघुर पेपर मिल्स कंपनी लिमिटेड बनाम उड़ीसा राज्य , (1983) 2 एससीसी 433; ग्लैक्सो स्मिथ क्लाइन कंज्यूमर हेल्थ केयर लिमिटेड बनाम असिस्टेंट कमिश्नर (सीटी) , (2020) 19 एससीसी 681; मृणमोय मैती बनाम छंदा कोले , 2024 एससीसी ऑनलाइन एससी 551;त्रिदीप कुमार डिंगल बनाम स्टेट ऑफ डब्ल्यूबी , (2009) 1 एससीसी 768

अधिनियमों की सूची

वित्त अधिनियम, 1994; भारत का संविधान

मुख्य शब्दों की सूची

विलम्ब और विलंब; वैकल्पिक उपाय; सेवा कर; न्याय निर्णय आदेश; रिट क्षेत्राधिकार; अनुच्छेद 226; वित्त अधिनियम; सीमा; वैधानिक उपाय; अत्यधिक विलम्ब।

प्रकरण से उत्पन्न

दिनांक 31.10.2014 का अधिनिर्णय आदेश 03.11.2014 को दिया गया, धारा 86 के तहत अपील नहीं की गई, पांच साल बाद रिट द्वारा चुनौती दी गई।

पक्षकारों की ओर से उपस्थिति

याचिकाकर्ता/ओं के लिए:	श्री डी.वी.पथी, वरीय अधिवक्ता श्री हिरेश करण, अधिवक्ता श्री विवेकानंद, अधिवक्ता श्री सदाशिव तिवारी, अधिवक्ता सुश्री शिवानी देवाला, अधिवक्ता सुश्री प्राची पल्लवी, अधिवक्ता
प्रतिवादी/ओं के लिए:	डॉ. के. एन. सिंह, एएसजी ।

श्री अंशुमन सिंह,वरीय स्थायी सलाहकार,
सी.जी.एस.टी. और सी. एक्स.

श्री शिवादित्यधारी सिन्हा,अधिवक्ता
श्री आलोक कुमार, अधिवक्ता
श्री गिरिजीश कुमार, अधिवक्ता
बैंक के लिए: श्री के. के. सिन्हा, अधिवक्ता
श्री दीनबंधु सिंह, अधिवक्ता

हेडनोट्स रिपोर्टर द्वारा तैयार किया गयाः आकांक्षा मालवीय, अधिवक्ता

पटना उच्च न्यायालय का निर्णय/आदेश

पटना उच्च न्यायालय के न्यायाधिकरण में

2019 की दीवानी रिट क्षेत्राधिकार मामला सं. 13976

==========

अपने सहभागी श्री शैलेंद्र कुमार शर्मा, पिता-चंद्रिका शर्मा, निवासी 462, नेहरू नगर, डाकघर और थाना-पाटलिपुत्र, पटना-800013 के माध्यम से मेसर्स प्रकृति एंटरप्राइजेज 462, नेहरू नगर, पाटलिपुत्र, पटना-800013।

.....याचिकाकर्ता/ओं

बनाम

1. सीजीएसटी एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क के मुख्य आयुक्त, प्रथम तल, एनेक्सी केंद्रीय राजस्व भवन, बीरचंद पटेल पथ, पटना-800001
2. प्रधान आयुक्त, सीजीएसटी एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, पटना-I, तृतीय तल, एनेक्सी केंद्रीय राजस्व भवन, बीरचंद पटेल पथ, पटना-800001
3. सहायक/उप आयुक्त, सीजीएसटी एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, पटना (मध्य) प्रभाग, बैंक रोड, गांधी मैदान, पटना-800001
4. बिहार राज्य, प्रधान सचिव, शिक्षा विभाग, नया सचिवालय, पटना के माध्यम से
5. राज्य परियोजना निदेशक, बिहार शिक्षा परियोजना परिषद, शिशका भवन, सैदपुर, पटना-800004
6. शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, किदवईपुरी शाखा, किदवईपुरी, पटना-800001 (आई. एफ. एस. सी. एस. बी. आई. एन.0004142)

.....प्रतिवादी/ओं

==========

उपस्थिति :

याचिकाकर्ता/ओं के लिए: श्री डी.वी.पथी, वरीय अधिवक्ता
श्री हिरेश करण, अधिवक्ता
श्री विवेकानंद, अधिवक्ता
श्री सदाशिव तिवारी, अधिवक्ता
सुश्री शिवानी देवाला, अधिवक्ता
सुश्री प्राची पल्लवी, अधिवक्ता

प्रतिवादी/ओं के लिए: डॉ. के. एन. सिंह, एएसजी ।
श्री अंशुमन सिंह,वरीय स्थायी सलाहकार, सी.जी.एस.टी. और सी. एक्स.
श्री शिवादित्यधारी सिन्हा,अधिवक्ता
श्री आलोक कुमार, अधिवक्ता

श्री गिरिजीश कुमार, अधिवक्ता

बैंक के लिए: श्री के. के. सिन्हा, अधिवक्ता

श्री दीनबंधु सिंह, अधिवक्ता

==========

.

गणपूर्ति:माननीय न्यायमूर्ति श्री पी. बी. भजंत्री

और

माननीय न्यायमूर्ति श्री एस. बी. प्रसाद सिंह

मौखिक निर्णय

(द्वारा:माननीय न्यायमूर्ति श्री पी. बी. भजंत्री)

तिथि:18-06-2025

तत्काल रिट याचिका में, याचिकाकर्ता ने निम्नलिखित राहतों के लिए प्रार्थना की हैः

"(क) यह कि मांग सह कारण दिखाएँ नोटिस सी. सं. वी. (39) 10-लेखा परीक्षा/आई. एन. वी./2010/भाग-I/3182, दिनांक 23/04/2013, (अनुलग्नक में निहित -3) अवैध और क्षेत्राधिकार के बाहर होने के कारण निरस्त किया जाए।

(ख) वित्त अधिनियम, 1994 की धारा 87 के अधीन दिनांक 10/05/2019 को निर्गत सूचना (अनुलग्नक-5 में निहित), भारतीय स्टेट बैंक, एस. के. पुरी शाखा (आई. एफ. एस. सी. एस. बी. आई. एन. 0004142) के अंतर्गत, सी. सं. वी (30) 321/ए. आर. सी./सी. जी. एस. टी./पी. डी./2019/1767 याचिकाकर्ता के बैंक (चालू) खाता संख्या 34963114466 और बैंक (चालू) खाता संख्या 10636207919 को कुर्क करने के लिए कार्यवाही शुरू करना, अवैध, अधिकार क्षेत्र के बिना और मौलिक अधिकार के साथ-साथ संवैधानिक अधिकार का उल्लंघन है और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत का भी उल्लंघन है।

(ग) कि किसी अन्य वैध अनुतोष की अनुमति दी जा सकती है जिसके लिए याचिकाकर्ता हकदार है।

2. याचिकाकर्ता एक फर्म है जो राज्य सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली केंद्रीय प्रायोजित योजना सेवाओं के तहत कुछ सामान और सेवाएं प्रदान करती है। बिहार शिक्षा परियोजना परिषद (बीएसपीपी), सोसायटी और याचिकाकर्ता - मेसर्स प्रकृति एंटरप्राइजेज के बीच 19.06.2007 को एक समझौता हुआ था। उन्होंने सामान के साथ सेवा निष्पादित की है जैसा कि अनुबंध की अवधि, कार्यकारी मॉडल, भुगतान शर्तें,

स्वामित्व/हस्तांतरण, संशोधन, प्रतिपक्ष, अप्रत्याशित घटना, मध्यस्थता और सामान्य जैसे विभिन्न खंडों के साथ पढ़े गए समझौते के पैराग्राफ नंबर 1 से स्पष्ट है। अनुबंध तीन साल की अवधि के लिए था। इसे वर्ष 2011-2012 में निष्पादित और पूरा किया गया था, दूसरे शब्दों में, 2007-2008 (अक्टूबर, 2007 से मार्च, 2008 तक) से वर्ष 2011-2012 की अवधि के लिए। उपर्युक्त समझौते के निष्पादन के लिए, याचिकाकर्ता अपनी फर्म को पंजीकृत करने में विफल रहा है, नतीजतन, वह संबंधित प्रतिवादियों/विभाग में सेवा कर की गणना और प्रेषण करने में विफल रहा है। इस संबंध में, 23.04.2013 को मांग सह कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। याचिकाकर्ता ने 25.03.2014 को अपना स्पष्टीकरण/जवाब प्रस्तुत किया था जो प्रतिवादियों/विभाग द्वारा संतुष्ट नहीं था, इस प्रकार 31.10.2014 को अंतिम आदेश पारित करने के लिए आगे बढ़ा और इसे 03.11.2014 को याचिकाकर्ता को सूचित किया गया था जबकि याचिकाकर्ता ने वित्त अधिनियम, 1994 (इसके बाद 'अधिनियम, 1994' के रूप में संदर्भित) की धारा 86 के तहत अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष अपील का उपाय नहीं किया है। इस प्रकार, वर्तमान रिट याचिका 19.06.2019 को दायर की गई थी।

3. याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि अधिनियम, 1994 की धारा 73 (4-बी) का उल्लंघन हुआ है और यह सीमा अवधि के संबंध में है और इसमें दो भाग हैं, अर्थात् 12 महीने और 5 वर्ष की अवधि सीमा। जहाँ तक 5 वर्ष की अवधि का संबंध है, यदि कोई गलत बयानी/धोखाधड़ी आदि है, तो विभाग द्वारा 5 वर्ष की अवधि को ध्यान में रखा जा सकता है। यह भी प्रस्तुत किया गया है कि इसी तरह के मामले माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष ***भारत संघ एवं अन्य बनाम जीएमआर एयरपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड*** के ***विशेष अनुमति अपील (सी) संख्या 5392/2025*** के मामले में विचाराधीन हैं, इसलिए, मामले का निर्णय उपर्युक्त माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के निपटारे के बाद किया जाना आवश्यक है।

4. *इसके विपरीत*, प्रतिवादियों के विद्वान अधिवक्ता ने प्रारंभिक आपत्ति जताई कि याचिकाकर्ता की ओर से कारण दर्शाओ नोटिस दिनांक 23.04.2013 और इसके परिणामस्वरूप दिनांक 31.10.2014 के आदेश और वर्ष 2019 में आगे की कार्रवाई में देरी और लापरवाही की गई है। यह भी प्रस्तुत किया जाता है कि अंतिम आदेश याचिकाकर्ता को 03.11.2014 को सूचित किया गया था। इसके अलावा, वह अधिनियम, 1994 की धारा 86 के तहत अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष अपील के उपाय को लागू करने में विफल रहे हैं। दूसरी ओर, याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने प्रतिवादियों के उपरोक्त तर्क का जवाब देते

हुए कहा कि अधिनियम, 1994 की धारा 73 (4-बी) के उल्लंघन को देखते हुए देरी और विलंब का सवाल नहीं उठता। यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि दिनांक 31.10.2014 का आदेश याचिकाकर्ता को सूचित नहीं किया गया है। अनुच्छेद 226 के तहत यह न्यायालय मामले के तथ्यों के आलोक में देरी और विलंब को नजरअंदाज कर सकता है।

5. संबंधित पक्षों के लिए विद्वान अधिवक्ताओं को सुना।

6. प्रतिवादियों की ओर से उठाया गया प्रारंभिक मुद्दा यह है कि रिट याचिका पर सीमाएं और प्रतिबंध हैं। समय-समय पर न्यायालयों ने यह अभिनिर्धारित किया है कि विलंब और बाधाओं की जांच रिट न्यायालयों द्वारा की जानी चाहिए और इसलिए वैकल्पिक वैधानिक उपचार को समाप्त नहीं करने के लिए भी। वर्तमान मामले में, याचिकाकर्ता को 31.10.2014 को कार्रवाई का कारण प्राप्त हुआ, जबकि रिट याचिका जून, 2019 के महीने में दाखिल किया गया था। याचिकाकर्ता के पास अधिनियम, 1994 की धारा 86 के तहत अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष अपील का एक वैधानिक उपाय था और वह समाप्त नहीं हुआ है। अधिनियम, 1994 की धारा 86 को पुनः प्रस्तुत करना आवश्यक है और यह निम्नानुसार हैः

"86. अपीलीय न्यायाधिकरण में अपील-(1) कोई भी केंद्रीय आबकारी के 10 [आयुक्त] द्वारा [धारा 73 धारा 83ए [XXX]] के तहत पारित आदेश या धारा 85 के तहत केंद्रीय आबकारी (अपील) के [आयुक्त] द्वारा पारित आदेश से व्यथित निर्धारिती ऐसे आदेश के खिलाफ "आदेश प्राप्त होने की तारीख के तीन महीने के भीतर" अपीलीय न्यायाधिकरण में अपील कर सकता है।

[(1क) (i) बोर्ड, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, ऐसी समितियों का गठन कर सकता है जो इस अध्याय के प्रयोजनों के लिए आवश्यक हों।

(ii) खंड (i) के तहत गठित प्रत्येक समिति में, यथास्थिति, केंद्रीय आबकारी के दो मुख्य आयुक्त या केंद्रीय आबकारी के दो आयुक्त होंगे।

[(2)[केंद्रीय आबकारी के मुख्य आयुक्तों की समिति], यदि वह केंद्रीय आबकारी आयुक्त द्वारा [धारा 73 या धारा 83ए [XXX]] के तहत पारित किसी भी आदेश पर आपत्ति करती है, तो केंद्रीय आबकारी आयुक्त को आदेश के खिलाफ अपीलीय न्यायाधिकरण में अपील करने का निर्देश दे सकती है।

[बशर्ते कि जहां केंद्रीय आबकारी के मुख्य आयुक्तों की समिति केंद्रीय आबकारी आयुक्त के आदेश के खिलाफ अपनी राय में भिन्न होती है, वह उस बिंदु या बिंदु को बताएगी जिस पर वह भिन्न है और बोर्ड को एक संदर्भ देगी, जो आदेश

के तथ्यों पर विचार करने के बाद, यदि यह राय है कि केंद्रीय आबकारी आयुक्त द्वारा पारित आदेश कानूनी या उचित नहीं है, तो केंद्रीय आबकारी आयुक्त को आदेश के खिलाफ अपीलीय न्यायाधिकरण में अपील करने का निर्देश देगा।

[(2क) आयुक्तों की समिति, यदि वह धारा 85 के तहत केंद्रीय आबकारी आयुक्त (अपील) द्वारा पारित किसी भी आदेश पर आपत्ति करता है, तो किसी भी केंद्रीय आबकारी अधिकारी को आदेश के खिलाफ अपीलीय न्यायाधिकरण में अपनी ओर से अपील करने का निर्देश दे सकती है:]

[बशर्ते कि जहां आयुक्तों की समिति केंद्रीय आबकारी आयुक्त (अपील) के आदेश के खिलाफ अपनी राय में भिन्न होती है, वह उस बिंदु या बिंदुओं को बताएगी जिन पर वह भिन्न है और क्षेत्राधिकार वाले मुख्य आयुक्त को संदर्भित करेगी, जो आदेश के तथ्यों पर विचार करने के पश्चात्, यदि उनकी राय में केंद्रीय आबकारी आयुक्त (अपील) द्वारा पारित आदेश कानूनी या उचित नहीं है, तो किसी भी केंद्रीय आबकारी अधिकारी को आदेश के खिलाफ अपीलीय न्यायाधिकरण में अपील करने का निर्देश दें।

स्पष्टीकरण— इस उप-धारा के प्रयोजनों के लिए, "क्षेत्राधिकार वाले मुख्य आयुक्त" का अर्थ है उस मामले में संबंधित न्यायनिर्णायक प्राधिकारी पर अधिकारिता रखने वाला मुख्य आयुक्त।]

[(3) "उप-धारा (2) या उप-धारा (2ए) के तहत प्रत्येक अपील उस तारीख से चार महीने के भीतर दायर की जाएगी जिस दिन मुख्य आयुक्तों की समिति या, जैसा भी मामला हो, आयुक्तों की समिति द्वारा अपील करने का आदेश प्राप्त किया जाता है।";]

(4) [केंद्रीय आबकारी आयुक्त या 15 [जैसा भी मामला हो, कोई केंद्रीय आबकारी अधिकारी] या निर्धारिती, इस सूचना की प्राप्ति पर कि केंद्रीय आबकारी आयुक्त या केंद्रीय आबकारी आयुक्त (अपील) के आदेश के खिलाफ अपील उप-धारा (1) या उप-धारा (2) या उप-धारा (2ए) के तहत दूसरे पक्ष द्वारा की गई है, इस बात के बावजूद कि उसने ऐसे आदेश या उसके किसी हिस्से के खिलाफ अपील नहीं की है, नोटिस प्राप्त होने के पैंतालीस दिनों के भीतर, निर्धारित में सत्यापित प्रति-आपत्तियों का ज्ञापन दायर कर सकता है। केंद्रीय आबकारी के [आयुक्त] या केंद्रीय आबकारी (अपील) के [आयुक्त] के आदेश के किसी भी हिस्से के खिलाफ, और ऐसे ज्ञापन का निपटान अपीलीय न्यायाधिकरण द्वारा इस तरह किया

जाएगा जैसे कि यह उप-धारा (3) में निर्दिष्ट समय के भीतर प्रस्तुत की गई अपील हो।

(5) अपीलीय न्यायाधिकरण उप-धारा 1 या उप-धारा 3 या उप-धारा 4 में निर्दिष्ट प्रासंगिक अवधि की समाप्ति के बाद अपील स्वीकार कर सकता है या प्रति-आपत्तियों का ज्ञापन दाखिल करने की अनुमति दे सकता है, यदि यह संतुष्ट है कि उस अवधि के भीतर इसे प्रस्तुत नहीं करने का पर्याप्त कारण था।

(6) अपीलीय न्यायाधिकरण में एक अपील निर्धारित प्रपत्र में होगी और निर्धारित तरीके से सत्यापित की जाएगी और सेवा कर और ब्याज की मांग की तारीख या जुर्माना लगाने की तारीख, जिसके संबंध में अपील की गई है, के बावजूद, शुल्क के साथ होगी –

क) जहां सेवा कर और ब्याज की राशि की मांग की गई है और किसी केंद्रीय आबकारी अधिकारी द्वारा उस मामले में लगाया गया जुर्माना, जिससे अपील संबंधित है, पांच लाख रुपये या उससे कम है, वहाँ एक हजार रुपये;

ख) जहां अपील से सम्बंधित मामले में किसी केंद्रीय आबकारी अधिकारी द्वारा मांग की गई सेवा कर और ब्याज की राशि और जुर्माना पांच लाख रूपये से अधिक परन्तु पचास लाख रूपये से अधिक नहीं है,वहाँ पांच हजार रूपये।

ग) जहां अपील से सम्बंधित किसी केंद्रीय आबकारी अधिकारी द्वारा मांगी गई सेवा कर और ब्याज की राशि और जुर्माना पचास लाख रुपये से अधिक है, वहाँ दस हजार रुपयेः

बशर्ते कि उप-धारा (2) या उप-धारा (2ए) में निर्दिष्ट अपील या उप-धारा (4) में निर्दिष्ट प्रति-आपत्तियों के ज्ञापन के मामले में कोई शुल्क देय नहीं होगा।

(6क) अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष किया गया प्रत्येक आवेदन,

क) रोक लगाने या गलती सुधारने या किसी अन्य उद्देश्य के लिए अपील में; या

ख) किसी अपील या आवेदन की बहाली के लिए, पाँच सौ रुपये का शुल्क साथ होगाः

बशर्ते कि इस उप-धारा के तहत केंद्रीय आबकारी आयुक्त या केंद्रीय आबकारी के सहायक आयुक्त या केंद्रीय आबकारी के उपायुक्त द्वारा दायर आवेदन के मामले में ऐसा कोई शुल्क देय नहीं होगा।] (7) इस अध्याय के प्रावधानों के अधीन

रहते हुए, इस धारा के तहत अपील की सुनवाई और आदेश देने में, अपीलीय न्यायाधिकरण उन्हीं शक्तियों का प्रयोग करेगा और उसी प्रक्रिया का पालन करेगा जो वह 4 [केंद्रीय आबकारी अधिनियम, 1944] (1944 का 1) के तहत अपीलों की सुनवाई और आदेश देने में करता है।

7. वैधानिक अपील निर्धारित समय सीमा के भीतर दायर की जानी आवश्यक है। अपील दायर करने से बचने के लिए, वर्तमान रिट याचिका याचिकाकर्ता को उपार्जित कार्रवाई के कारण की तारीख से लगभग पांच साल बाद दायर की गई है। इस संबंध में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय अर्थात ***जम्मू और कश्मीर बनाम आर.के.जलपुरी और अन्य ए. आई. आर. 2016 एस. सी. 3006,*** में प्रतिवेदित कंडिका संख्या 20 में इसे निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया गया हैः

"20. इस प्रकार कहने के बाद, शहर और औद्योगिक विकास निगम बनाम दोसू आर्देशिर भिवंडीवाला और अन्य (2009) 1 एस. सी. सी. 168), से एक अंश का उल्लेख करना उपयोगी होगा। जिसमें इस न्यायालय ने संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत अधिकारिता पर विचार करते हुए इस प्रकार व्यक्त किया गया हैः-

"न्यायालय अनुच्छेद 226 के तहत अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए इस बात पर विचार करने के लिए कर्तव्यबद्ध है कि क्याः

(क) रिट याचिका के निर्णय में तथ्यों का कोई भी जटिल और विवादित प्रश्न शामिल है और क्या उन्हें संतोषजनक रूप से हल किया जा सकता है;

(ख) याचिका सभी भौतिक तथ्यों को प्रकट करती है;

(ग) <u>याचिकाकर्ता के पास विवाद के समाधान के लिए कोई वैकल्पिक या प्रभावी उपाय है;</u>

(घ) <u>अधिकार क्षेत्र का आह्वान करने वाला व्यक्ति अस्पष्टीकृत देरी और बाधाओं का दोषी है;</u>

(ड्) सीमा के किसी भी कानून द्वारा प्रत्यक्ष रूप से वर्जित;

(च) राहत देना सार्वजनिक नीति के खिलाफ है या किसी वैध कानून द्वारा वर्जित है; और कई अन्य कारक हैं

रेखांकित आपूर्ति की गई

8. माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा एक अन्य निर्णय में अपील उपचार को समाप्त नहीं करने और समय सीमा के भीतर वैधानिक अपील दायर नहीं करने और रिट याचिका दायर करने में कार्रवाई को दूर करने के लिए समान विचार लिए गए हैं।इस तरह के वाद मनोरंजक नहीं हैं। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ***सहायक आयुक्त (सी. टी.) एल. टी. यू., काकीनाडा और अन्य बनाम मेसर्स ग्लैक्सो स्मिथ क्लाइन कंज्यूमर हेल्थ केयर लिमिटेड (2020) 19 एस. सी. सी. 681*** के मामले में कंडिका संख्या 1,14,15 और 16 में, यह निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया जाता हैः

"1. अनुमति प्रदान की गई। इस अपील में विवादास्पद प्रश्न ग्लैक्सो स्मिथ क्लाइन कंज्यूमर हेल्थकेयर लिमिटेड बनाम सी. सी. टी [ग्लैक्सो स्मिथ क्लाइन कंज्यूमर हेल्थकेयर लिमिटेड बनाम.सी. सी. टी., 2018 एस. सी. सी. ऑनलाइन हाईड 1985] में दिनांक 19-11-2018 के निर्णय और आदेश से उत्पन्न होता है। जो तेलंगाना राज्य और आंध्र प्रदेश राज्य के लिए हैदराबाद में उच्च न्यायालय द्वारा पारित (संक्षेप में "उच्च न्यायालय") है:क्या उच्च न्यायालय को भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत अपने रिट अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए मूल्यांकन आदेश को केवल इस आधार पर चुनौती देनी चाहिए कि उस आदेश के खिलाफ अपील का वैधानिक उपचार परिसीमा कानून द्वारा रोक लगा दी गई थी?

14. इन तथ्यों की पृष्ठभूमि में, मुख्य प्रश्न यह है कि क्या उच्च न्यायालय को प्रतिवादी द्वारा दायर रिट याचिका पर विचार करना चाहिए था?जहाँ

तक भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए निर्देश, आदेश या रिट जारी करने की उच्च न्यायालय की शक्ति का संबंध है, वही अब एकीकृत नहीं है। भले ही उच्च न्यायालय संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत राज्य द्वारा पारित किसी भी आदेश या निर्देश/कार्रवाई के खिलाफ एक रिट याचिका पर विचार कर सकता है, लेकिन निश्चित रूप से ऐसा तब नहीं करना चाहिए जब पीड़ित व्यक्ति कानून द्वारा निर्धारित तरीके से एक प्रभावी वैकल्पिक उपाय का लाभ उठा सकता था (देखें बाबूराम प्रकाश चंद्र माहेश्वरी बनाम अंतरम जिला परिषद [बाबूराम प्रकाश चंद्र माहेश्वरी बनाम अंतरम जिला परिषद, ए. आई. आर. 1969 एस. सी. 556] और निवेदिता शर्मा बनाम सी. ओ. ए. आई. [निवेदिता शर्मा बनाम सी. ओ. ए. आई., (2011) 14 एस. सी. सी. 337:(2012) 4 एस. सी. सी. (सी. आई. वी.) 947])थानसिंह नाथमल बनाम कर अधीक्षक के मामले में [थानसिंह नाथमल बनाम पुलिस अधीक्षक ए. आई. आर. 1964 एस. सी. 1419,इस न्यायालय की संविधान पीठ ने यह स्पष्ट कर दिया कि यद्यपि संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय की शक्ति बहुत व्यापक है, न्यायालय को स्वयं लगाए गए प्रतिबंध का प्रयोग करना चाहिए और रिट याचिका पर विचार नहीं करना चाहिए, यदि पीड़ित व्यक्ति के लिए कोई वैकल्पिक प्रभावी उपाय उपलब्ध है। कंडिका 7 में न्यायालय ने इस प्रकार टिप्पणी कीः(थानसिंह नाथमल मामला [थानसिंह नाथमल बनाम पुलिस कर अधीक्षक, ए. आई. आर. 1964 एस. सी. 1419], ए. आई. आर. पी.1423)

> *"7. आयुक्त के आदेश के खिलाफ संदर्भ के लिए एक आदेश का दावा किया जा सकता था यदि अपीलार्थी आयुक्त या उच्च न्यायालय को संतुष्ट करते कि आदेश से कानून का प्रश्न उत्पन्न होता है। लेकिन उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को लागू करने के*

लिए अधिनियम द्वारा प्रदान की गई प्रक्रिया को अपास्त कर दिया गया, अपीलकर्ताओं ने बिक्री की अवधारणा को बढ़ाने के लिए प्रांतीय विधानमंडल की क्षमता को चुनौती देते हुए उच्च न्यायालय का रुख किया, और अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय के असाधारण अधिकार क्षेत्र को लागू किया और तथ्य के प्रश्न पर कर अधिकारियों के निर्णय को फिर से खोलने की मांग की।संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय का अधिकार क्षेत्र व्यापक रूप से जुड़ा हुआ है और इसका प्रयोग अनुच्छेदों में स्पष्ट रूप से प्रदान किए गए क्षेत्रीय प्रतिबंधों के अलावा किसी भी प्रतिबंध के अधीन नहीं हैं। लेकिन अधिकार क्षेत्र का प्रयोग विवेकाधीन है:इसका प्रयोग केवल इसलिए नहीं किया जाता है कि ऐसा करना विधिसम्मत है। अधिकार क्षेत्र के विस्तार की मांग है कि इसका उपयोग आम तौर पर कुछ स्व-लागू सीमाओं के अधीन किया जाएगा। उस अधिकार क्षेत्र का सहारा लेना राहत के लिए एक वैकल्पिक उपाय के रूप में अभिप्रेत नहीं है जो किसी वाद या क़ानून द्वारा निर्धारित अन्य तरीके से प्राप्त किया जा सकता है। आम तौर पर न्यायालय अनुच्छेद 226 के तहत एक रिट के लिए याचिका पर विचार नहीं करेगा, जहां याचिकाकर्ता के पास एक वैकल्पिक उपाय है, जो अनावश्यक रूप से कठिन होने के बिना, एक समान रूप से प्रभावी उपाय प्रदान करता है। फिर से उच्च न्यायालय आम तौर पर उन प्रश्नों के निर्धारण पर प्रवेश नहीं करता है जो उस अधिकार को स्थापित करने के लिए साक्ष्य की विस्तृत जांच की मांग करते हैं जिसे लागू करने का दावा किया जाता है। इसलिए उच्च न्यायालय तथ्य की त्रुटियों को सुधारने के लिए किसी न्यायालय

या न्यायाधिकरण के निर्णय के खिलाफ अपील न्यायालय के रूप में कार्य नहीं करता है, और राहत प्राप्त करने के लिए क़ानून द्वारा प्रदान किए गए वैकल्पिक उपाय पर अनुच्छेद 226 के तहत अधिकार क्षेत्र को ग्रहण करके कार्य नहीं करता है। जहां व्यथित याचिकाकर्ता के लिए किसी अन्य न्यायाधिकरण में जाने का अधिकार है, या किसी क़ानून द्वारा प्रदान किए गए तरीके से निवारण प्राप्त करने के लिए खुद भी किसी अन्य क्षेत्राधिकार में, उच्च न्यायालय आम तौर पर संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत एक याचिका पर विचार करके क़ानून के तहत बनाए गए तंत्र को अपास्त करने की अनुमति नहीं देगा, और आवेदन करने वाले पक्ष को इस तरह से स्थापित तंत्र का सहारा लेने के लिए छोड़ देगा।

(जोर दिया गया)

15. हम उपयोगी रूप से टीटाघुर पेपर मिल्स कंपनी लिमिटेड बनाम टीटाघुर पेपर मिल्स कंपनी लिमिटेड में इस न्यायालय के स्पष्टीकरण का उल्लेख कर सकते हैं। उड़ीसा राज्य [टीटाघुर पेपर मिल्स कं. लिमिटेड बनाम उड़ीसा राज्य (1983) 2 एस. सी. सी. 433:1983 एस. सी. सी. (कर) 131], जिसमें यह देखा गया है कि जहां किसी कानून द्वारा कोई अधिकार या दायित्व बनाया गया है, जो इसे लागू करने के लिए एक विशेष उपाय देता है, तो उस कानून द्वारा प्रदान किए गए उपाय का लाभ केवल लिया जाना चाहिए। कंडिका 11 में न्यायालय ने इस प्रकार टिप्पणी कीः(एस. सी. सी. पीपी. 440-41)

"11. अधिनियम की योजना के तहत, अधिकारियों का एक पदानुक्रम है जिसके समक्ष याचिकाकर्ता शिकायत किए गए गलत कार्यों के खिलाफ पर्याप्त निवारण प्राप्त कर सकते हैं।

याचिकाकर्ताओं को अधिनियम की धारा 23 की उप-धारा (1) के तहत निर्धारित प्राधिकरण के समक्ष अपील करने का अधिकार है। यदि याचिकाकर्ता अपील में निर्णय से असंतुष्ट हैं, तो वे अधिनियम की धारा 23 की उप-धारा (3) के तहत न्यायाधिकरण में आगे की अपील कर सकते हैं, और फिर अधिनियम की धारा 24 के तहत उच्च न्यायालय की राय के लिए कानून के प्रश्न पर मामला प्रस्तुत करने के लिए कह सकते हैं। अधिनियम में मूल्यांकन के आदेश को चुनौती देने के लिए एक पूर्ण तंत्र प्रदान करता है, और मूल्यांकन के आक्षेपित आदेशों को केवल अधिनियम द्वारा निर्धारित तरीके से चुनौती दी जा सकती है, ना कि संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत याचिका द्वारा।अब यह अच्छी तरह से मान्यता प्राप्त है कि जहां किसी क़ानून द्वारा कोई अधिकार या दायित्व बनाया जाता है जो इसे लागू करने के लिए एक विशेष उपाय देता है, केवल उस क़ानून द्वारा प्रदान किए गए उपाय का लाभ उठाया जाना चाहिए। इस नियम को विल्स, जे. द्वारा वॉल्वरहैम्प्टन न्यू वाटरवर्क्स कंपनी बनाम था। हॉक्सफोर्ड [वॉल्वरहैम्प्टन न्यू वाटरवर्क्स कं. बनाम हॉक्सफोर्ड, (1859) 6 सी. बी. एन. एस. 336,356:141 ई. आर. 486] में बहुत स्पष्टता के साथ कहा गया था। निम्नलिखित गद्यांश में हैः

'ऐसे मामलों की तीन श्रेणियां हैं जिनमें कानून के आधार पर देयता स्थापित की जा सकती है।... लेकिन एक तीसरा वर्ग है अर्थात जहां एक देयता जो सामान्य कानून में मौजूद नहीं है, एक क़ानून द्वारा बनाई गई है जो उसी समय इसे लागू करने के लिए एक विशेष और विशेष उपाय प्रदान करती है।... कानून द्वारा प्रदान

किए गए उपाय का पालन किया जाना चाहिए, और यह पक्षों के लिए द्वितीय श्रेणी के मामलों पर लागू होने वाले तरीकों को अपनाना सक्षम नहीं है। कानून द्वारा दिए गए प्रपत्र को अपनाया जाना चाहिए और उसका पालन किया जाना चाहिए।'

इस परिच्छेद में निर्धारित नियम को नेविल बनाम लंदन एक्सप्रेस न्यूजपेपर लिमिटेड [नेविल बनाम लंदन एक्सप्रेस न्यूजपेपर लिमिटेड, 1919 एसी 368 (एचएल)] में हाउस ऑफ लॉर्ड्स द्वारा अनुमोदित किया गया था और त्रिनिदाद और टोबैगो के अटॉर्नी जनरल बनाम गॉर्डन ग्रांट एंड कंपनी लिमिटेड [त्रिनिदाद और टोबैगो के अटॉर्नी जनरल बनाम गॉर्डन ग्रांट एंड कंपनी लिमिटेड, 1935 एसी 532 (पीसी)] और राज्य सचिव बनाम मास्क एंड कंपनी [राज्य सचिव बनाम मास्क एंड कंपनी, 1940 एस. सी. सी. ऑनलाइन पी. सी. 10:ए. आई. आर. 1940 पी. सी. 105] में प्रिवी काउंसिल द्वारा पुनः पुष्टि की गई है। इसे अधिकारों के प्रवर्तन के लिए भी समान रूप से लागू माना गया है, और इस न्यायालय द्वारा पूरे समय इसका पालन किया गया है। इसलिए उच्च न्यायालय ने रिट याचिकाओं को सीमित रूप से खारिज कर दिया।.

(जोर दिया गया)

मफतलाल इंडस्ट्रीज लिमिटेड बनाम भारत संघ [मफतलाल इंडस्ट्रीज लिमिटेड बनाम भारत संघ, (1997) 5 एस. सी. सी. 536], में बाद के निर्णय में इस न्यायालय ने आगे कहा कि कोई अधिनियम संविधान के अनुच्छेद 226 या 32 के तहत उपचार को रोक और कम नहीं कर सकता है। हालाँकि, न्यायालय ने

सावधानी का एक शब्द जोड़ा और स्पष्ट किया कि संवैधानिक न्यायालय निश्चित रूप से अधिनियम के प्रावधानों में प्रकट विधायी इरादे पर ध्यान देगा और अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करेगा। इसे अलग तरह से रखने के लिए, तथ्य यह है कि उच्च न्यायालय के पास संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत व्यापक अधिकार क्षेत्र है, इसका मतलब यह नहीं है कि यह एक क़ानून के मूल प्रावधानों की अवहेलना कर सकता है और आदेश पारित कर सकता है जिसे केवल क़ानून द्वारा निर्धारित तंत्र के माध्यम से निपटाया जा सकता है।

16. निस्संदेह, संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय की शक्तियां व्यापक हैं, लेकिन निश्चित रूप से संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत इस न्यायालय को दी गई पूर्ण शक्तियों से अधिक व्यापक नहीं। अनुच्छेद 142 पक्षकारों को पूर्ण न्याय देने के लिए संविधान के तहत संपूर्ण न्यायिक शक्तियों का एक समूह और भंडार है। उस शक्ति का प्रयोग करते समय भी, इस न्यायालय को विधायी इरादे को ध्यान में रखना आवश्यक है न कि वैधानिक प्रावधान को अनुचित बनाना।ओ. एन. जी. सी. बनाम गुजरात ऊर्जा पारेषण निगम लिमिटेड [ओ. एन. जी. सी. बनाम गुजरात ऊर्जा पारेषण निगम लिमिटेड, (2017) 5 एससीसी 42: (2017) 3 एस. सी. सी. (सी. आई. वी.) 47], मामले में इस न्यायालय की तीन न्यायाधीशों की पीठ के हालिया निर्णय में, इस न्यायालय के समक्ष दायर वैधानिक अपील को 71 दिनों के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया था और बिजली अधिनियम, 2003 की धारा 125 के संदर्भ में देरी को माफ करने के लिए अधिकतम समय-सीमा केवल 60 दिन थी।दूसरे शब्दों में, अपील 60 दिनों की क्षम्य अवधि से परे प्रस्तुत की गई थी।नतीजतन, यह न्यायालय 71 दिनों की देरी को माफ नहीं कर

सकता था।विशेष रूप से, अपील को स्वीकार करते हुए, न्यायालय ने अपील दायर करने में देरी को माफ कर दिया था। हालाँकि, अपील की अंतिम सुनवाई में, अपील को सीमा द्वारा वर्जित किए जाने के संबंध में एक आपत्ति को एक अधिकार क्षेत्र का मुद्दा होने के कारण उठाए जाने की अनुमति दी गई थी और उक्त आपत्ति पर विचार करते हुए, न्यायालय ने सिंह एंटरप्राइजेज बनाम सीसीई [सिंह एंटरप्राइजेज बनाम सीसीई, (2008) 3 एससीसी 70], सीसीई बनाम होंगो (इंडिया) (पी) लिमिटेड [सीसीई बनाम होंगो (इंडिया) (पी) लिमिटेड, (2009) 5 एससीसी 791], छत्तीसगढ़ एसईबी बनाम सीईआरसी [छत्तीसगढ़ एसईबी बनाम सीईआरसी, (2010) 5 एस सी. सी. सी. 23] और सूर्यचक्र पावर कार्पोरेशन लिमिटेड वी.विद्युत विभाग।[सूर्यचक्र पावर कार्पोरेशन लिमिटेड वी.विद्युत विभाग।, (2016) 16 एससीसी 152:(2017) 5 एस. सी. सी. (सी. आई. वी.) 761] और निष्कर्ष निकाला कि सीमा अधिनियम, 1963 की धारा 5 को न्यायालय द्वारा विद्युत अधिनियम की धारा 125 में अधिकतम निर्धारित अवधि से अधिक अपील बनाए रखने के लिए लागू नहीं किया जा सकता है।

***मृणमय मैती बनाम छंदा कोले और अन्य* 2024 एस. सी. सी. ऑनलाइन एस. सी. 551** में प्रतिवेदित मामले के कंडिका संख्या 9, 10, 11, में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया हैः

9. उठाये गए प्रतिद्वंद्वी तर्कों को सुनने और वर्तमान मामले में प्राप्त तथ्यों को देखने के बाद, हमारा विचार है कि रिट याचिकाकर्ता को गैर-उपयुक्त होना चाहिए था या दूसरे शब्दों में रिट याचिका को देरी के आधार पर खारिज कर दिया जाना चाहिए था। एक आवेदक जो देर से या अन्य कारणों से न्यायालय का दरवाजा खटखटाता है दुसरे शब्दों में, काफी समय तक अपने अधिकारों के बारे में नहीं सोचते हैं, अपनी गहरी नींद से जागने पर रिट न्यायालयों द्वारा विशेष राहत नहीं दी जानी चाहिए।इस न्यायालय ने बार-बार यह अभिनिर्धारित किया है कि विलम्ब समता को पराजित करता है।भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत

विवेकाधीन शक्तियों का प्रयोग करते समय उच्च न्यायालय द्वारा ध्यान में रखे जाने वाले कारकों में से एक देरी या रुकावटें हैं। किसी मामले में, उच्च न्यायालय अपनी असाधारण शक्तियों का उपयोग करने से इनकार कर सकता है यदि आवेदक की ओर से अपने अधिकार का दावा करने में ढिलाई ने कार्रवाई के कारण को दूर करने की अनुमति दी है और बाद में कार्रवाई के व्यपगत कारण को फिर से जगाने के प्रयास किए जाते हैं।

10. विवेक का प्रयोग सावधानी और सावधानी के साथ किया जाएगा।यदि रिट अदालत का दरवाजा खटखटाने में हुई देरी की व्याख्या की जाती है जो अदालत की अंतरात्मा को अपील करेगी, तो ऐसी परिस्थितियों में चुनाव लड़ने वाले पक्ष द्वारा यह नहीं कहा जा सकता है कि आने वाले सभी समय के लिए देरी को माफ नहीं किया जाना चाहिए। ऐसी असंख्य परिस्थितियाँ हो सकती हैं जो असाधारण अधिकार क्षेत्र के आह्वान को जन्म देती हैं और यह सब प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर निर्भर करता है, इसे गणितीय सटीकता के साथ एक सीधे सूत्र में वर्णित नहीं किया जा सकता है। रिट अदालत द्वारा प्रयोग किया जाने वाला अंतिम विवेकाधिकार इन तथ्यों पर निर्भर करता है कि उसे यात्रा करनी है या जिस क्षेत्र में तथ्यों ने यात्रा की है।

11. रिट याचिका दायर करने के लिए, इसमें कोई संदेह नहीं है कि सीमा की कोई निश्चित अवधि निर्धारित नहीं है। हालांकि, जब रिट अदालत के असाधारण अधिकार क्षेत्र को लागू किया जाता है, तो यह देखा जाना चाहिए कि क्या एक उचित समय के भीतर इसे लागू किया गया है और यहां तक कि स्मारकों को प्रस्तुत करने से कार्रवाई के मृत कारण को पुनर्जीवित नहीं किया जाएगा या कार्रवाई के कारण को पुनर्जीवित नहीं किया जाएगा जिसकी प्राकृतिक मृत्यु हुई है। ऐसी परिस्थितियों में केवल विलंब और रुकावटों के आधार पर, अपील को खारिज कर दिया जाना चाहिए या आवेदक गैर-उपयुक्त होना चाहिए। यदि यह पाया जाता है कि रिट याचिकाकर्ता विलंब और विलंब का दोषी है, तो उच्च न्यायालय को याचिका को उसी एकमात्र आधार पर खारिज कर देना चाहिए, जहां तक कि रिट न्यायालय ऐसे लापरवाह वादी को अपनी गलती का लाभ उठाने की अनुमति देने में लिप्त नहीं हैं। यह सच है कि मौलिक अधिकार की कोई छूट नहीं हो सकती है, लेकिन अनुच्छेद 226 के तहत विवेकाधीन अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए, उच्च न्यायालय को अनिवार्य रूप से एक रिट न्यायालय का दरवाजा खटखटाने में आवेदक की ओर से

देरी और अड़चनों को ध्यान में रखना होगा।इस न्यायालय ने त्रिदीप कुमार डिंगल बनाम डब्ल्यू. बी. राज्य, (2009) 1 एस. सी. सी. 768 के मामले में निम्नलिखित प्रभाव को अभिनिर्धारित किया हैः

> *"56. हम विवाद को कायम रखने में असमर्थ हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है कि मौलिक अधिकार की कोई छूट नहीं हो सकती है। लेकिन संविधान के अनुच्छेद 32,226,227 या 136 के तहत विवेकाधीन अधिकारिता का प्रयोग करते हुए, यह न्यायालय कुछ कारकों को ध्यान में रखता है और ऐसे विचारों में से एक रिट अदालत का दरवाजा खटखटाने में आवेदक की ओर से देरी है। यह अच्छी तरह से तय किया गया है कि रिट जारी करने की शक्ति विवेकाधीन है। संविधान के अनुच्छेद 32 या 226 के तहत राहत देने से इनकार करने का एक आधार यह है कि याचिकाकर्ता देरी और लापरवाही का दोषी है।*
>
> *57. यदि याचिकाकर्ता एक रिट न्यायालय के अधिकार क्षेत्र का आह्वान करना चाहता है, तो उसे जल्द से जल्द उचित रूप से संभव अवसर पर न्यायालय में आना चाहिए।रिट के लिए प्रस्ताव देने में अत्यधिक देरी वास्तव में इस तरह के विवेकाधीन अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करने से इनकार करने के लिए एक अच्छा आधार होगा।इस सिद्धांत का अंतर्निहित उद्देश्य पुराने दावों के आंदोलन को प्रोत्साहित करना और उन मामलों को बाहर निकालना नहीं है जिन्हें पहले ही निस्तारण या सुलह किया जा चुका है या जहां इस बीच तीसरे पक्ष के अधिकार अर्जित हो चुके हैं (एम. पी. राज्य बनाम भाईलाल भाई, [ए. आई. आर. 1964 एस. सी. 1006:(1964) 6 एस. सी. आर. 261], मून मिल्स लिमिटेड बनाम.औद्योगिक न्यायालय, [ए. आई. आर. 1967 एस. सी. 1450] और भूप सिंह बनाम भारत संघ, [(1992) 3 एस. सी. सी. 136: (1992) 21 एटीसी 675:(1992) 2 एससीआर 969])।यह सिद्धांत मौलिक अधिकार के उल्लंघन के मामले में भी लागू होता है (तिलकचंद मोतीचंद बनाम एच. बी. मुंशी, [(1969) 1 एस. सी. सी. 110], दुर्गा प्रसाद बनाम आयात और निर्यात के मुख्य नियंत्रक,*

[(1969) 1 एस. सी. सी. 185] और रवींद्रनाथ बोस बनाम भारत संघ, [(1970) 1 एस. सी. सी. 84])।

58. कोई ऊपरी सीमा नहीं है और इसकी कोई निचली सीमा नहीं है अब प्रत्येक व्यक्ति न्यायालय का दरवाजा खटखटा सकता है। प्रश्न विवेकाधीन होता है और इसका निर्णय न्यायालय के समक्ष तथ्यों के आधार पर किया जाता है जो मामले-दर-मामले पर निर्भर करता है और भिन्न होता है।यह इस बात पर निर्भर करेगा कि मौलिक अधिकार का उल्लंघन क्या है और दावा किए गए उपाय क्या हैं और देरी कब और कैसे हुई है।

इन तथ्यों और परिस्थितियों के आलोक में, वर्तमान रिट याचिका की स्थिरता से संबंधित प्रारंभिक मुद्दे पर, विलंब और बाधाओं के आधार पर, याचिकाकर्ता ने ऐसा कोई मामला नहीं बनाया है जिससे प्रतिवादियों की आक्षेपित कार्रवाई में हस्तक्षेप किया जा सके। तदनुसार, वर्तमान रिट याचिका खारिज होने योग्य है।

9. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ***तमिलनाडु सीमेंट्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड बनाम सूक्ष्म एवं लघु उद्यम सुविधा परिषद एवं अन्य (2025) 4 एससीसी 1*** में दर्ज मामले में, पैराग्राफ संख्या 54 से 63 में रिट याचिका की स्वीकार्यता का विश्लेषण किया है, जहाँ वैकल्पिक उपाय या उपायों की समाप्ति हो, जबकि यह माना गया है कि रिट न्यायालय, वैकल्पिक उपाय के अस्तित्व के बावजूद, निम्नलिखित मामलों में अधिकार क्षेत्र का प्रयोग कर सकता है: (i) प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन; (ii) बिना अधिकार क्षेत्र के कार्यवाही में आदेश; (iii) अधिनियम की शक्तियों को चुनौती दी गई हो; या (iv) क़ानून के तहत उपाय भारी या बोझिल हो, जैसे कि जहाँ पक्ष को अपील दायर करने से पहले कर की पूरी राशि जमा करने की आवश्यकता होती है। वर्तमान मामले में, यदि याचिकाकर्ता ने उचित समयावधि के भीतर संपर्क किया होता, तो हम उपर्युक्त सिद्धांतों की जाँच कर सकते थे। दूसरी ओर, याचिकाकर्ता लगभग पाँच वर्षों तक दायर करने में हुई अनुचित देरी और

लापरवाही का स्पष्टीकरण नहीं दे सका। इसलिए, लापरवाही के आधार पर, याचिकाकर्ता ने कोई मामला नहीं बनाया है।

10. याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने दलील दी कि यह मामला माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है, जहाँ तक अधिनियम, 1994 की धारा 73 (4-बी) की व्याख्या का संबंध है, यह वर्तमान मामले में सहायक नहीं होगा क्योंकि याचिकाकर्ता इस मामले पर लगभग पाँच वर्षों से सो रहा है, इसलिए इस मामले को उपरोक्त निर्णय के निपटारे तक स्थगित करना उचित नहीं है, जिसका निर्णय गुण-दोष के आधार पर किया जाना आवश्यक है। दूसरी ओर, हम याचिकाकर्ता की ओर से देरी और लापरवाही के प्रारंभिक मुद्दे पर वर्तमान रिट याचिका पर निर्णय लेने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। अतः, वर्तमान सीडब्ल्यूजेसी संख्या 13976/2019 खारिज की जाती है।

(पी. बी. भजंत्री, न्यायाधीश)
(एस. बी. प्रा. सिंह, न्यायाधीश)

गौरव एस./-

खंडन (डिस्क्लेमर)- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नही किया जा सकता । समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।